

संपादक की कलम से

ईवीएम आंदोलन में विपक्ष अनुपरिथित

पिछले करीब 5 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर देश भर में संशय का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि ये मशीनें सही नहीं देती और इसे हैक किया जा सकता है। उनका आरोप है कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आई है तभी से इनका जमकर दुरुपयोग हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष के कोई संगठन व नेता आवाजें तो उठाते रहे हैं परन्तु इसे लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, जिसकी जरूरत इसलिये महसूस की जाती है व्यक्तिगत सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के द्वारा अन्य संगठनों की ओर से इस पर उठाये गये सवालिय निशानों का संतोषजनक उत्तर नहीं देती। अब इस मुद्दे पर दिल्ली में वरिष्ठ वकील सदूकों पर उत्तर आये हैं। कुछ सिविल सोसायटियों के लोग भी हैं पर इन आंदोलनों में जिनकी मुख्य शिरकत होनी चाहिये, वे सिरे से नदारद हैं—यानी विपक्षी दल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानुप्रताप सिंह, महमूद प्राचा, सत्यप्रकाश गौतम आदि निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी 50 वोटिंग मशीनें दिलाई जायें ताकि वे उन्हें हैक करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर सकें और इसका धारणा को मिटा सकें कि ऐसा नहीं किया जा सकता। आयोग को इस विषय पर एक पत्र भी लिखा गया था जिसके जवाब में आयोग ने साफ किया कि मशीनें

विश्वसनीय हैं। आदोलनकारी आयुक्त से मिलने का समय भी मांगते रहे जो उन्हें दिया ही नहीं गया। वैसे तो ईवीएम की गड़बड़ियों पर लम्बे समय से शक होता रहा परन्तु वह तब गहराता और पुख्ता होता गया जब बहुत से राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित निकलते गये। जमीनी स्तर पर हालात कुछ और दिखते थे जबकि परिणाम इतने अलग निकले कि स्वयं जीतने वाले उम्मीदवार चौंक पड़ते थे। नवम्बर, 2023 के छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के चुनाव उदाहरण हैं। सारे विशेषक, पत्रकार, यहा तक कि आम जनता भी मानकर चल रही थीं कि तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। नतीजे एकदम विपरीत निकले। पिछले कुछ समय के अनेक राज्यों के चुनाव भी गिनाये जा रहे हैं जहां समझा जाता था कि भाजपा की जीत असम्भव है। फिर भी उसे विजय मिली। उत्तर प्रदेश में 2022 के प्रारम्भ में हुए चुनाव में उन इलाकों में भी भाजपा के प्रत्याशी जीते जहां विभिन्न कारणों से माहौल उसके खिलाफ था। लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नावाचक तथा

आदि ऐसी ही सीटें थीं। भाजपा की केन्द्र सरकार ईवीएम के पक्ष में डटकर खड़ी है। उसका दावा है कि मशीनें एकदम ठीक हैं और प्रतिपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का आदी है। इसके लिये हर चुनाव के पहले ईवीएम का विमर्श स्वयं भाजपा यह कहकर छेड़ देती है कि 'अगर भाजपा जीती तो विपक्षी दल ईवीएम का रोना रोएंगे'। इसके बावजूद कई लोगों की हृद मान्यता है कि भाजपा की लगातार जीत के पीछे

इसका बोधार्हुद कई लोगों का दृष्टि नाम्भारा है कि भाजपा का लोगाना भारत का पाठ्य-इन्हीं मशीनों का हाथ है जिसे इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है कि ज्यादातर सेवों भाजपा के पक्ष में ही जाते हैं। कई भाजपा नेता तक कहते पाये गये हैं कि वोट किसी को भी दीजिये, मिलेगा तो भाजपा को ही। भाजपा की नीति पर शक्ति इसलिये होता है क्योंकि भाजपा के ही एक नेता जीएल नरसिंहा राव ने 2010 में ईवीएम पर एक किताब लिखी थी 'डेमोक्रेसी एट रिस्क', जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईवीएम से चुनाव कराना गलत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इसकी भूमिका में लिखा था कि 'ईवीएम पर धैर्य लगाना लोकतंत्र को मजबूत करना है'। वहीं भाजपा अब इसके खिलाफ सुनने के लिये तैयार नहीं है।
इस दौरान एक और बात उठती रही है। वह है 19 लाख ईवीएम की गुमशुदगी

कहा जाता है कि विभिन्न राज्यों में ये मशीनें ही भाजपा की मर्जी के नतीजे देती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कह नहीं सकते लेकिन इस पर सरकार का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अगर मशीनें वाकई गायब हैं तो उसे खोना निकालना होगा। इतनी तादाद में गुम मशीनें कोई भी निर्णय पलट सकती हैं। इसमें वीवीपीट का पक्ष भी अहम है। यह वह रसीद होती है जो बतलाती है कि वोट किसे दिया गया है। वह एक पर्ची के रूप में मतदाता को दिखता है। पहले यह पर्याप्त अवधित तक दिखलाई पड़ता था, परन्तु अब वह 6-7 सेकंड के लिये दिखता है और उसकी पारदर्शिता घटा दी गयी है। ईर्वीएम विरोधियों का तर्क है कि अगर मशीनें से ही चुनाव कराना हो तो पर्वी गोटर के हाथ में आये जिसे वह खुद बॉक्स में डाले और इसी की गिनती हो। आयोग को यह इस आधार पर मजूर नहीं किया इससे परिणाम 3-4 दिन देर से निकलेंगे। यह तर्क इसलिये हास्यास्पद है क्योंकि कई बार नतीजे महीने भर बाद निकलते हैं। मशीनों का इस्तेमाल कई देश बन्द कर चुके हैं। भाजपा का इसके प्रति मोह व आग्रह शंकाओं को गहराता है।

असली सवाल यह है कि इन आंदोलनों में विषय क्या है? इंडोएम को कार्यक्रम गढ़बढ़ियों का सर्वाधिक नुकसान उठे हैं। वर्कलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना नहीं है फिर भी वे सड़कों पर हैं। फिर, विरोधी दल इस आंदोलन में क्यों नहीं है? कुछ नेताओं ने बयानबाजी की है पर वह नाकामी है।

हवाई जहाज के किनारे भोजन उप्र सबका साथ सबका विकास

- सर्वमित्रा सुरजन ये हिंदू के जागेन का ही असर है कि अब मोदीजी को सबका साथ, सबका विकास के बादे को पूरा करने में आसानी हो रही है। प्रधानमंत्री परंभालने पर उन्होंने कहा था कि देश में ऐसा विकास कर देंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाईयात्रा कर सकेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को अच्छे जूते पहनने लायक बना देंगे यानी लोग जिस हाल में हैं, उसी हाल में या उससे बुरे हाल में कर देंगे बस उन्हें हवा में उड़ने का सुख नहीं हो सकेगा। हवाई जहाज के यात्रियों ने हवाई जहाज के बगल में, रनवे की जमीन पर बैठकर भोजन किया। ऐसा महान दृश्य इस महान देश ने कभी नहीं देखा था। पुराने जमाने में जब हवाई जहाज कम हुआ करते थे और गिने-चुने लग ही हवाई यात्रा करते थे, तब जो लोग हवाई जहाज पर चढ़ नहीं पाए थे, वो हवाईयात्रियों को विमान की सीढ़ी तक छोड़ देने और लेने जाया करते थे। यात्रियों के स्वागत और विदाइ के लिए गेंद की फूल-मालाएं हाथ में लेकर लोग जाते थे और दिल में एक हसरत भी कि काश कभी हम भै ड़ान भरने का सुख प्राप्त कर पाते। ये तो नेहरूजी जब तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश के लाखों लोगों को विमानयात्रा से वर्चित रखा। हवा में उड़ने का आनंद देने की जगह आम लोगों के लिए न जाने क्या आईआईटी, आईआईएम बनवाए, इलाज, खेती, विज्ञान जैसे गैरजरस्टर्स क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया। सार्वजनिक निकाय खड़े किए ताकि लोगों को सरकारी नौकरियां मिल सकें। और अब जब सरकार नौकरी नहीं देता रहा है, तो चंद देशद्रोही मोदी सरकार पर ही उन्हें बेरोजगार रखने का इलाजाम लगा रहे हैं। जबकि सारी गलती नेहरू की है। आरएसएस के आर्थिक संगठन ग्रन्ट एवं डेवलपमेंट जनरल्स मंजू के मार्गेजनल अपिली एजन्स ने दर्शे

संगठन स्वदेशा जागरण मच क सयाजक आश्वाना महाजन न इस पूर्व
विस्तार से समझाया है।
श्री महाजन ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण लोगों
सरकारी नौकरियों के पाठे भागने लगे। हर साल करोड़ों लोग नौकरी
बाजार में आते हैं न तो सरकार और न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतने
नौकरियां दे सकती हैं। इससे निपटने का एकमात्र तरीका उद्यमियों को तैयार
करना है। भारत कभी उद्यमियों का देश था। हमें उस भारत का पुनर्निर्माण
करना है, और यह केवल बड़े पैमाने पर समाज के सहयोग से ही हो सकता
है। इस कथन की व्याख्या यही समझ आती है कि अब बेरोजगारों
के आंकड़े जारी करने और उन पर चिंता जाहिर करने का कोई अर्थ नहीं
है। क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। मोदीजी ने चुनाव की रोटी में
भले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, लेकिन बाद में
उन्होंने पकड़ा तलक देश के पुनर्निर्माण में योगदान की राह दिखा दी थी।
संघ उसी राह पर अब भारत का ले जाना चाहता है। इसलिए वह समाज

गरीबी के अभिशाप से मुक्ति की ओर अग्रसर भारत



आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत एवं विकसित भारत को निर्मित करते हुए गरीब एवं गरीबीमुक्त भारत के संकल्प की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि एवं ऐतिहासिक सफलता है। नीति आयोग के अनुसार जीवन स्तर सुधार, शिक्षा व चिकित्सा की उपलब्धता के आधार पर देश में कुल 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। विगत नौ वर्ष में ऐसी गरीबी कल्याण की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे भारत के भाल पर लगे गरीबी के शर्म के कलंक को धोने के सार्थक प्रयत्न हुए हैं एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों को ऊपर उठाया गया है।

आजादी के 75 साल बाद भी भारत के समने जो सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी रही हैं, इनमें गरीबी सबसे प्रमुख है। यही कारण है कि वर्ष 2047 के आजादी के शताब्दी समारोह के लिये जो योजनाएं एवं लक्ष्य तय किये हैं, उनमें गरीबी उन्मूलन के लिये भी व्यापक योजनाएं बनायी गयी हैं। गरीबी के अधिकारी से देश की एक बड़ी आबादी को निकालने के लिए मोदी सरकार के प्रयत्न निश्चित ही सराहनीय है। नीति आयोग के मुताबिक देश में वर्ष 2013-14 में बहुआयामी गरीबी 29.17 फीसदी थी जो वर्ष 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई है। बहुआयामी गरीबी के आंकड़े जुटाते समय पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों के मापदंडों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार भी गरीबी से बाहर आने की स्थितियों के मूल्यांकन का आधार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सालों में इन तीनों ही मोर्चों पर देश में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए समानता,

सुलन एवं गरबा उन्मूलन का काफी काम हुआ है। इसी का नतीजा है कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में हर्ष एवं उल्लास की यह खबर दी गई है कि बीते नौ साल के दैरेन करीब पच्चीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। देश की विशाल आबादी के इस बढ़े हिस्से से जुड़ा यह आंकड़ा इसलिए भी राहत देने वाला कहा जा सकता है कि कभी ह्याँमारुङ्ग राज्य कहे जाने वाले बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सरीखे राज्यों में गरीबी में सबसे ज्यादा कमी आई है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत के लिये गरीबी से बाहर आना एवं गरीबी के कलंक को धोना जरूरी है। यह माना भी जाता है कि किसी भी देश का अर्थिक विकास लोगों में समृद्धि लाने वाला होता है। लेकिन, यही समृद्धि जब अर्थिक असमानता का प्रतीक बन जाए तो चिंता का सबब एवं त्रासदी बन जाती है। चिंता इस बात की भी रही है कि आजादी के प्रारंभिक पचास वर्षों की सरकारों के समाने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य कोरा भाषणों, नारों एवं दिखावे का रहा, यही कारण है कि उस दर में विकास जरिए होने वाली अर्थिक समृद्धि फायदा भी गिने-चुने हाथों में पहुंच रहा है। गरीब और गरीब एवं अमर और अमर होने हुए देखे गये। इतरह की राजनीतिक प्रेरित योजना गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सब ज्यादा बाधक बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसर देश में आतंकवादी वारदातें बढ़ोने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, सरकार के ईमानदारी और पारादिश से काम करने के साथ उनका सरकार ने गरीबों के कल्याण लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च किया है और 13.5 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। निश्चित ही भारत से गरीबी दूर हो रही है। इन सुखद आंकड़ों के साथ देशवासियों को ?इस बात का अहसास कराया जा रहा है कि जब देश अर्थिक रूप से मजबूत होता है तो तिजोरी ही नहीं भरती बल्कि वे का सामर्थ्य भी बढ़ता है। ?निश्चित गरीबी के अभिशाप को पूरी तरह समाप्त करने के लिये परिवारवादी भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ने की जरूरत है क्योंकि गरीब, पिछड़े, आदिवासियों तथा

दालता का हक छानत है, इन गरीब को समात हो जाते हैं लेकिन गरीबी नहीं। वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-21 के मोदी सरकार के 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की संख्या 32.59 फीसदी से घटकर 19.28 फीसदी रह गई है। इसी अवधि के दौरान शहरी इलाके में गरीबी 8.65 फीसदी से 5.21 फीसदी रह गई है। नीति आयोग ने ताजे आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएचजनधन योजना और समग्र शिक्षा वेचलते भी देश में गरीबी कम हुई है और लोगों का जीवन बदला है। इसके बावजूद अभी भी देश में एक बड़ा तबका है, जो बुनियात सुविधाओं के अभाव वाला जीवन जीने को मजबूर है। यह स्पष्ट संकेत है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद गरीब उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने वेळे लिए नए विचारों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर विमर्श के साथ गरीबों के लिये आर्थिक स्वावलम्बन स्वरोजगार की आज देश को सख्त

जरूरत है। गरबा का मृत्यु का रेविडिया बाटने एवं उनके वोट बटोरने की स्वार्थी राजनीतिक मानसिकता से उपरत होकर ही गरीबीमुक्त संतुलित समाज संरचना की जा सकती है। सतत गरीबी उन्मूलन के लिये व्यापक कार्य किया जाना अपेक्षित है। नया भारत-सशक्त भारत बनाने की जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगों के हाथों में ही बहुत सारी पूँजी इकट्ठी हो जाये, पूँजी का वितरण ऐसा होना चाहिए कि विशाल देश के लाखों गांवों एवं करोड़ों लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन क्या कारण है कि महात्मा गांधी को पूँजे वाला पूर्व सत्ताशीर्ष का नेतृत्व उनके ट्रस्टीशीप के सिद्धान्त को बड़ी चतुराई से किनारे करता रहा है। यही कारण है कि एक और अमीरों की ऊंची अद्वालिकाएं हैं तो दूसरी ओर फुटपाथों पर रेंगती गरीबी। एक ओर वैभव ने व्यक्ति को विस्तीर्णी और विस्तीर्ण ते

पाकासा, खालीन सहत कर दिया में प्रगति की है। भारत विश्व में आर्थिक रूप से संपन्न 5 देशों में शामिल हो चुका है। श्रीराम मन्दिर प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही गरीबी के आंकड़ों में गिरावट से दुनिया हैरान हो रही और यह अमृत काल की अमृत उपलब्धि है। फिर भी कल्याणकारी योजनाओं व आर्थिक संबल के अलावा भी देश को स्वावलम्बी बनाने, महंगाई व बेरोजगारी की चुनौतियों के दक्षतापूर्ण एवं कुशल प्रबंधन की जरूरत है। आर्थिक विकास का लाभ समाज के विचित्र और शोषित वर्ग तक सुलभ होता रहे, यह अपेक्षित है। इसके लिये मोदी सरकार बिना शेर-शराबे के गरीबी उन्मूलन के मिशन पर लगी है, जिसके आश्वयकारी एवं सुखद परिणामों से देशवासी ही नहीं, दुनिया भी स्तंभित होती रहेगी।

प्रेषक:

ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन,
पटपड़गंज, दिल्ली-92

डिजीटल युग के लिए खतरनाक है डीपफेक (सम-सामयिक)



आज विज्ञान ३०० और तकनीक का युग है और विज्ञान तथा तकनीक का उद्देश्य यह रहा है कि इससे मानव जीवन बेहतर और अच्छा बने। सब तो यह है कि मानव समाज की प्राप्ति, उसका उत्तरार्थ विकास ही विज्ञान और तकनीक का असली उद्देश्य रहा है लेकिन आज के समय में विज्ञान और तकनीक दोनों का ही मानव द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीक मानव के लिए वरदान है तो अभिशाप भी साथित हुई है। डीपफेक इन दिनों काफी चर्चा में है मनोरंजन के उद्देश्य से मनोरंजक वीडियो और तस्वीरें बनाना ही डीपफेक का एकमात्र उपयोग नहीं है। जो गीज़ शौकिया प्रयोग के रूप में शुरू हुई थी वह अब एक संभावित खतरनाक तकनीक बन गई है।

2014 में किया गया था और इस गुडफ्लॉल और उसकी टीम ने पेश किया था। डॉपफेक में अमर्तौर पर ढीप लर्निंग एलोरिदम ड्रापफक वाडया नहा बना सकत ह, लाक्ष समर्थ्या यह है कि आजकल डॉपफेक बन से जड़े अनेक एप्स मौजूद हैं जिनकी मद्दत

के 1.2 अरब उपयोगकर्ता थे। इसमें से 75 करोड़ स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं डेलॉयट के 2022 ग्लोबल टीएमर्टी (प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन दूसरंचार) अनुमान के अनुसार, हायपरेशन बाजार में 2026 तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर एक अरब पर पहुंचने का अनुमान है। इन डेलॉयट के विश्लेषण के अनुसार, भारतीय स्मार्टफोन की मांग सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 2026 में 40 करोड़ हो जाएगी, जो 2021 में 30 करोड़ थी। ऐसे में एंड्रॉयड फोन के इस युग में डीपक रंग बचना बहुत ही जरूरी है। एंड्रॉयड फोन वेकारण आज आर्थिक अपराध भी काफी बढ़ गए हैं। लोगों के बैंक खतों स्थाली हो रहे हैं

**निरंतर परिश्रम, सायम और
महत्वाकांक्षा सफल व्यक्ति के सच्चे मित्र**

जिदगी का मूल ही निरंतर संघर्ष श्रम सकल्प और प्रगति है। सकारात्मक उद्देश्य को लेकर किया गया श्रम सदैव श्रेष्ठ परिणाम देता है। श्रम और संघर्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। निरंतर श्रम करना उच्च मनोबल बनाए रखना और सफलता की कामना और पवित्र महत्वाकांक्षा सफल मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं जीवन है चलने का नाम, गति का नाम ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क जी मानव वो मनोबल अस्ति प्राप्त करता है। मानव जो

मास्तक हा मनुष्य का सृजनात्मक शाक प्रदान करता ह। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है। नावप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज में 3% नवाचार का निधारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है। पुराने समय से ही अर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुमुख होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके विचार करेंगे डॉलर के हो। वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है, बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है, जबकि भारत में यह तबाही लासकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जनरेक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास अर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाशात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित आचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा अर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

विदेश संदेश

22 जनवरी को नेपाल के तीन हजार से अधिक प्राचीन मंदिरों में होगी विशेष पूजा



काठमांडू। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन नेपाल के तीन हजार से अधिक मंदिरों में विशेष पूजा पाठ, हवन, भजन, कर्तन करने की तैयारी की गई है।

काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर सभी शक्तिपीठों में 22 जनवरी को विशेष पूजा की तैयारी की गई है। काठमांडू के ही बुद्धानिलकण्ठ मंदिर, गुहेश्वरी मंदिर, मैतीदेवी मंदिर, दश्मिकाली आदि शक्तिपीठों में सूबह के समय विशेष पूजा, तेहाहर का भजन कीर्तन और शाम को विशेष हवन किए जाने की तैयारी है। विशेष हिन्दू परिषद नेपाल के महासचिव निर्देशिका सिंह ने कहा कि काठमांडू सहित देश के सभी बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इन

सब कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। काठमांडू के अलावा मुक्तिनाथ मंदिर, पौखरा के विश्ववासिनी मंदिर, सप्तरी के छिनमस्ता भगवती मंदिर, सुनसरी जिले के दत्तकाली मंदिर, बांके जिला के बागेश्वरी मंदिर, सल्लान जिले के कमलाली, गोकर्ण के भैरवी मंदिर, दैतेख के ज्वालादेवी, पर्सा के गहवा माई मंदिर, बारा के गढीमाई मंदिर, मकवानपुर के मनोकमना मंदिर, तुवाकोट के जलपा देवी सहित एक हजार से अधिक प्रसिद्ध देवी मंदिरों में विशेष आयोजन रखा गया है। मंदिर, सल्लान जिले के कमलाली,

गोकर्ण के भैरवी मंदिर, दैतेख के ज्वालादेवी, पर्सा के गहवा माई मंदिर, बारा के गढीमाई मंदिर, मकवानपुर के मनोकमना मंदिर, तुवाकोट के जलपा देवी सहित एक हजार से अधिक प्रसिद्ध देवी मंदिरों में विशेष आयोजन रखा गया है। विशेष हिन्दू परिषद नेपाल के संगठन देखने को मिल रहा है।

नाटो 90,000 सैनिकों के साथ शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अभ्यास करेगा



बुमेल्स। नाटो शीत युद्ध के बाद से अपना सबसे बड़ा अभ्यास 'स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024' शुरू कर रहा है। इसमें निकट भविष्य में एक कारीगरी प्रतिष्ठान के साथ उभरते संघर्ष परिवर्ती को देखते हुए लोगों की सीमा से लगे देशों और गठबंधन के पूर्वी हिस्से में यूरोपीय सहयोगियों को कैरेस मजबूती प्रदान की जाएगी। इसका अभ्यास किया जाएगा।

गठबंधन के शीर्ष कमांडर क्रिस कैवोली ने गुरुवार को कहा कि लगभग 90,000 सैनिक स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास में शामिल होंगे, जो मई तक चलेगा। नाटो ने कहा है कि विमान कार्रवाई से लेकर विद्युतिक तक 50 से अधिक जहाज, साथ ही 80 से अधिक लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन और 133 टैक और 533 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों सहित कम से कम 1,100 लड़ाकू वाहन इस अभ्यास में भाग लेंगे।

पाकिस्तान का पलटवार, ईरान की सीमा में एयर स्ट्राइक का दावा



Spokesperson MoFA @ForeignOfficePk - 10h
... "Last night's unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law...Pakistan reserves the right to respond to this illegal act."

"Statement by the Spokesperson on Last Night's Violation of Pakistan's Sovereignty by Iran"

इस्लामाबाद। ईरान की तरफ से पाकिस्तान में किए गए ड्रोन व

अखण्ड भारत संदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी श्री योगी सत्यमं कौर योग संस्कृत समिति द्वारा विधिवाच इन्स्ट्राइब्रेज 1/6C माधव कुंज कठरा प्रयागराज से मुद्रित एवं क्रियायोग अश्रम एवं अनुरंगन संस्थान झूसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

स्वामी श्री योगी सत्यमं कौर योग संस्कृत समिति द्वारा विधिवाच इन्स्ट्राइब्रेज 1/6C माधव कुंज कठरा प्रयागराज से मुद्रित एवं क्रियायोग अश्रम एवं अनुरंगन संस्थान झूसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

सम्पादक स्वामी श्री योगी सत्यमं RNI No: UPHIN/2001/09025 ऑफिस नं.: 9565333000 Email:- akhandbharatsandesh1@gmail.com सभी विवादों का व्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मिसाइल हमले और दोनों देशों के बीच यारी राजनीयिक तनावनी के बीच पाकिस्तान ने तुरन्त बोला को दावा किया है कि वायुसेना ने हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने चेतावनी दी कि एकत्रफा कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति किया। ये ठिकाने पाकिस्तान में वायरिंट बोलच विद्रोहियों के थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुद्राबिकारी ठिकानों पर सिएपास्टन-ओ-बलचित्तान प्रांत में छिपे आतंकीयों के ठिकानों पर संबंधों में तनाव आ गया है। सटीक लक्षित हमलों की श्रृंखला शुरू की। इस कार्रवाई में कई आतंकीयों को घायल किया गया है। पाकिस्तान को राजदूत को निष्कासित कर दिया। साथ ही ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला के आधार पर वह कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का यह कदम ईरान के तरफ से 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोला करने की नीति पर चल रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की जीत पर चल रहा है।

पाकिस्तान को वीच से बोला करने की नीति पर चल रहा है। जिसमें ईरान की वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में बने आतंकी संगठन जैश-अल-अदल के दो ठिकानों पर

हमला किया था।

पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि वायुसेना ने अपनी राजदूत को जारी करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने चेतावनी दी कि एकत्रफा कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति प्रतिष्ठान के लिए हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। इन दिनों ईश्वरन को पिछले साल 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री लैंग के आदेश पर ईश्वरन के बेतन में 82 फौसदी की कटौती की गई थी। इन दिनों ईश्वरन जमानत पर है। हालांकि पायथंड मंत्री रहते ईश्वरन की कौविड महामारी के बाद सिंगापुर को एयर हब के रूप में पुनर्निर्माण को लेकर काफी प्रशंसा भी हुई थी।

देस मोइनेस (आयोवा)। अमेरिकी प्रांत आयोवा में मिली जीत से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गदगद हैं। उन्होंने जीत का जशन मनाते हुए कहा कि वह अमेरिका की सेवा के लिए बने हैं। ट्रम्प ने 2024 के चुनाव के पहले रिपब्लिकन प्राइमरी आयोवा कांकस में शनदार जीत हासिल की। उन्हें 51 प्रतिशत वोट मिले हैं। यह जीत उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर स्थायी पकड़ का स्पष्ट संकेत है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प की जीत के 30 अंकों के अंतर ने आयोवा रिपब्लिकन कॉकस में प्रतिस्पर्धा का एक रिकॉर्ड बाजारा है। रिपोर्ट के अनुसार, बावजूद इसके ट्रम्प को पूरे साल अदालती तारीखों का समान करना होगा। उनके खिलाफ 91 मामले दर्ज हैं। वह कल मानवनि मुकदमे के सिलसिले में न्यूयॉर्क कोट हाउस में उपस्थित हुए। यह मुकदमा

नेपाल ने 12 वर्षों में 28000 मेगावाट बिजली उत्पादन का रखा लक्ष्य



काठमांडू। नेपाल सरकार ने 12 वर्षों में 28000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत के साथ अगले 10 वर्षों में 10 हजार से अधिक मंदिरों को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है।

रेस्मी के मुताबिक इन मंदिरों के अलावा नेपाल में लगभग सभी जिलों में भगवान श्रीराम का भी मंदिर है। जहां 10 वर्षों की तैयारी की गई है। विशेष ज्ञान रखने वाले को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है। भारत के साथ दीर्घकालिक व्यापार समझौता होने के साथ ही इसको पूरा करने के लिए नई नीति बनाकर आगे बढ़ावे की आवश्यकता है। हाल ही में भारत के विशेष ज्ञान रखने वाले को बढ़ावा देने के लिए जारी की गयी नीति बनाकर आगे बढ़ावे की आवश्यकता है। हाल ही में भारत के विशेष ज्ञान रखने वाले को बढ़ावा देने के लिए जारी की गयी नीति बनाकर आगे बढ़ावे की आवश्यकता है।

हस्ताक्षर होने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादकों का उत्पादन भी बढ़ावा देना चाहिए। भारत के विशेष ज्ञान रखने वाले होने की आवश्यकता है। जानकारी दी जाएगी।

नेपाल की सभी जिलों की श्रीराम का भी मंदिर होने की आवश्यकता है। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी।

के उर्जा मंत्री ने कहा कि भारत की सरकारी कंपनी सलालज और एनटीपीजी सहित निजी क्षेत्र के जीएमआर गुप्त, अडाया गुप्त और रिलायंस एन्जी के प्रतिनिधियों से अलग-अलग जलविद्युत परियोजना में निवेश की चर्चा शुरू हुई है।

नेपाल की सभी जिलों की श्रीराम का भी मंदिर होने की आवश्यकता है। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी। जानकारी दी जाएगी।

सिंगापुर: भ्रष्टाचार के मामले में फंसे परिवहन मंत्री ईश्वरन का पद, पार्टी व पालियामेंट से इस्तीफा



डोनाल्ड ट्रम्प ने आयोवा कॉकस में जीत का जश्न मनाया, कहा-अमेरिका की सेवा के लिए बना हूं



लेखिका इं. जीन कैरोल से संबं